उनको compensation भी नहीं मिला है। सर, contractors यह कहते हैं कि यह compensation NHAI देगी। NHAI के पास हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके बारे में पूरा ब्यौरा बना कर भेज दिया है। यह कोई तीन करोड़ से भी ऊपर का compensation बन रहा है और लोगों को इसके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। सर, सर्दियां आ गई हैं, लेकिन अभी तक भी वे लोग अपने घरों को रिपेयर नहीं करवा सके हैं और उनको अभी तक उसका compensation नहीं मिला है। मैं सरकार से इस बात के लिए अनुरोध करती हूं कि उन लोगों को, जो जबली एरिया में पड़ते हैं, जो परवानू और सोलन के बीच में है, उस हाइवे पर पड़ते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी compensation दिया जाए, जिससे कि वे लोग अपने घरों की मरम्मत कर सकें और सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, जो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, उसके लिए भी जल्दी से प्रावधान किया जाए। आपका बहुत- बहुत धन्यवाद।

Need to release 1st and 2nd installment of amounts as per the Fourteenth Finance Commission for the Panchayat Samiti in Rajasthan

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान): माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन को, वित्त मंत्रालय को और संबंधित मंत्री को अवगत कराना चाहूंगा कि Fourteenth Finance Commission की रिकमंडेशंस के अनुसार rural development fast हो और उसको जल्दी वह राशि मिले, इसलिए यहां पर केन्द्र सरकार से एक फाइनेंशियल असिस्टेंस quarterly basis पर जाती है। इसी के तहत राजस्थान के अंदर 1,850 करोड़ रुपये second installment के गए। उस पैसे के जाने के बाद 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत को वह पैसा मिलना चाहिए, लेकिन हो यह रहा है कि ग्राम पंचायत को पैसा न देकर, उसको पंचायत समिति के पीडी एकाउंट में डाल देते हैं, जिससे कि उसका यूज कहीं भी दूसरी जगह पर किया जा सकता है - ऐसा कर दिया गया है। सर, 25 अक्टूबर को यहां से amount release हुआ है और 11 नवंबर को स्टेट गवर्नमेंट ने उसको पीडी एकाउंट में डलवा दिया है, लेकिन ग्राम पंचायतों को पैसा नहीं मिल रहा है।

दूसरा, अभी यह हो रहा है कि वे उसको 25 परसेंट, 50 परसेंट देने का मकसद है। इसका मकसद यह था कि rural development के लिए local bodies के द्वारा, ग्राम पंचायत के माध्यम से तुरंत उसका सदुपयोग हो, लेकिन वह नहीं हो रहा है। इसी के साथ-साथ, इसी तरह से राज्य द्वारा Fifth State Finance Commission के माध्यम से एक पंचायत को quarterly basis पर amount असिस्टेंस के रूप में दी जाती है। लेकिन आज करीब-करीब third quarter चला गया है, किन्तु उन्हें वह amount भी नहीं मिल रही है। इसलिए मैं वित्त मंत्रालय से विशेष रूप से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि 1,850 करोड़ रुपए, जो ग्राम के डेवलपमेंट के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से सीधे मिलने चाहिए, वह धनराशि राजस्थान में नहीं मिल रही है। मैं समझता हूं कि अन्य राज्यों ने भी कहीं न कहीं इस तरह की malpractice अपना रखी होगी, जिससे rural development प्रभावित होता है, धन्यवाद।

श्री राम नारायण डूडी (राजस्थान): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री नारायण लाल पंचारिया (राजस्थान): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती सम्पतिया उइके (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

DR. VIKAS MAHATME (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (Assam): Sir, I too associate myself with the mention made by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Seventy-Third and Seventy-Fourth Constitutional Amendments are very clear that the money should go directly into the account of the Gram Panchayats. So, this has to be taken note of by all States.

Need to set up the International Disaster Resilience and Risk Management Institute in Odisha

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Sir, recently, a Convention, under the auspices of the United Nations, was held in Delhi to combat desertification. Our hon. Prime Minister, who addressed the Convention, invited countries across the world to join Coalition for Disaster Resilient Infrastructure.

Sir, you would be astonished to know that every year in the world around 60,000 people die because of natural calamities. In our country also, many parts of India, including my State, Odisha, get severely affected by natural calamities every year like cyclones, avalanches, floods, earthquakes, droughts, Tsunami, etc. Serious losses to life and property occur every year. Particularly, States like Odisha are regular victim of such vagaries. You would be astonished to know that during the last Century, in the hundred years, Odisha was hit 78 times by different types of natural calamities, including cyclones. Not only our economy but our social fabric is also disturbed for that reason. Just in the last two decades, Odisha has witnessed many cyclones, storms,